औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) मुम्बई ने मेसर्स ए०एफ० फरगूसेन जो आई० डी० पी० एल० के उपचारात्मक अध्ययन के लिए सलाहकार है, को कार्य पर लगाया है।

(च) प्रचालन एजेन्सी नामतः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा आई० डी० पी० एल० के भविष्य पर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाना है।

Proposals from Private Sector Companies to set up Petro-Chemical Units in Andhra Pradesh

2918. DR. MOHAN BABU: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have received a number of proposals from private sector companies for setting up petro-chemical units in Andhra Pradesh;

(b) if so, the number of proposals received and the amount of investment involved; and

(c) when these proposals were received and the reasons for not granting licences for setting up the Units, so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SIS RAM OLA): (a) to (c) A proposal from M/s. H.C. Hydrocarbon and Petrochemicals Ltd. for setting up a 100% EOU Refinery cum Petrochemicals Complex in Andhra Pradesh was received in this Department in early 1996. Since the proposal related to the setting up of a Refinery Project and also carried a passing reference to Petrochemicals, this Department transferred the proposal to the Ministry of Petroleum and Natural Gas for appropriate action. At the same time M/s. H.C. Hydrocarbon were also informed that most of the information in their application relates to establishing of the Refinery. The Company was therefore advised to file a separate application for setting up of a Petrochemicals Complex indicating clearly the investment, value addition, details of sales, price and exports. M/s. H.C. Hydrocarbons have not furnished any further proposal to this Department.

Taking over of Mangalore Chemicals and Fertilizers Ltd. by KRIBHCO

2919. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that KRIBHCO has decided to take over the sick Mangalore Chemicals and Fertilizers Ltd.;

(b) if so, the details thereof; and

(c) by when it is proposed to be taken over?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS (SHRI SIS RAM OLA): (a) to (c) Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO) has submitted an offer for the rehabilitation of Mangalore Chemicals & Fertilizers Limited (MCFL) to the operating agency appointed by the Board for Industrial & Financial Reconstruction (BIFR). The proposal of KRIBHCO is subject to normal Government approvals. The final decision in the matter is contingent on the evaluation of the bids that may be received by the operating agency and the ultimate decision of the BIFR, which is a quasi-judicial authority.

Functioning of FCI's Units in Rajasthan

2920. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Fertilizer Corporation of India at Jodhpur and its units at Sri Mohangarh, Kawas, Nagaur and Hanumangarh in Rajasthan are running into losses for the last 5-6 years; and

(b) if so, the action taken by Government to make these units profitable and viable?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS (SHRI SIS RAM OLA): (a) The Jodhpur Mining Organisation (JMO) of fertilizer Corporation of India Ltd., which is located at Jodhpur is engaged in the mining of gypsum at Sri Mohangarh, Kawas and other areas in Rajasthan. Except for a marginal profit during 1991-92. Sri Mohangarh mines have incurred losses till 1995-96. The opeations in the Kawas mines have been profitable since 1990-91. The loss making mines located in Hanumangarh and Nagaur were surrender during the period from 1989 to 1994.

(b) The turnaround strategy of JMO is based on increasing its turnover and improving the operational efficiency.

आई०डी०पी०एल० को हुए घाटे

*2921. **श्री रामजी लाल**
श्री अजीत जोगी:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आई०डी०पी०एल०) को गत कई वर्षों से घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष हुए घाटे का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) कम्पनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है;

(ङ) क्या कम्पनी की वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि पिछले तीन महीनों से कर्मचारियों को वेतन और अन्य भुगतान नहीं किए जा रहे हैं; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या आई०डी०पी०एल० के **मजदूर संघों** ने कम्पनी कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए कोई प्रस्ताव पेश किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) जी हां। आई०डी०पी०एल० को 1993-94 में 70 करोड़ रु० का तथा 1994-95 में 77.52 करोड़ रु० का शुद्ध घाटा हुआ है। 1995-96 में 108 करोड़ रु० का अनंतिम शुद्ध घाटा हुआ है। इस रुग्णता का मुख्य कारण है अपर्याप्त बिक्री प्रयास, अत्यधिक जनशक्ति तथा परवर्ती रोजगार की उच्च लागत, आवश्यक स्तर पर कार्य करने की प्रक्रिया को प्राप्त करने में कम्पनी की असमर्थता, उच्च ब्याज का भार, उत्पाद-मिश्र (प्रोडक्ट मिक्स) में लचीलापन की कमी, अवरियात असुविधा इत्यादि हैं।

(ग) सरकार ने 1993-94 से 1995-96 तक कुल 148 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकार 1.4.1993 से पूंजीगत पुनःसंरचना के लिए भी सहमत है जिसमें 150 करोड़ रु० के बकाया ऋण का इक्यूईटी में परिवर्तित करना, बाकी ऋण को 7 वर्ष में भुगतेय मोरटेरिम के साथ ब्याज मुक्त ऋण में परिवर्तित करना तथा 285 करोड़ तक के ब्याज/जुर्माना ब्याज को समाप्त / माफ करना शामिल है।

(घ) और (ङ) आई० डी० पी० एल० को 1996-97 में अत्यधिक वित्तीय असुविधा हो रही है। चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने कम्पनी को 29.72 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता प्रदान की है। आई० डी० पी० एल० प्लांट में उत्पादन अक्टूबर 1996 से बन्द है। जनवरी 1997 में कर्मचारियों को भुगतेय दिसम्बर 1996 तक का वेतन तथा भत्तों का भुगतान कर दिया गया है।

(च) कर्मचारियों की ओर से दो योजनाएं पेश की गयी हैं, जो वास्तव में रूपरेखाएं हैं। दोनों योजनाओं में आई० डी० पी० एल० के पक्ष में केन्द्रीय सरकार मंत्रालयों/विभागों/अन्य संगठनों तथा राज्य सरकारों से अनन्य खरीद वरीयता की बात कही गई है। वह अनन्य वरीयता खरीद अद्यतन नीति के अनुरूप नहीं है। इन योजनाओं में नई देयताओं तथा रोकड़ घाटे के निधियन इत्यादि के साथ अद्यतन देयताओं को पूरा करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

Ban on the Production, use and Import of Plastic

2922. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that plastic bags, packaging materials etc. are eco-hostile, as reported in the "Hindustan Times" dated the 22nd February, 1996 and "Indian Express" dated the 9th December, 1996;